भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं. 3646**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए द्विपक्षीय समझौते

3646. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पड़ोसी और संबंद्ध देशों के साथ व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए किन्हीं नए द्विपक्षीय समझौतों का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ख) जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला और जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हाल की बहुपक्षीय पहलों से भारत को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत इस समय यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, ओमान, आस्ट्रेलिया (भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार करार पर व्यापक सहमति बनाने पेरू और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) पर वार्ताएं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अपने मौजूदा मुक्त व्यापार करारों, नामतः भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) और आसियान-भारत वस्तु व्यापार करार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा भी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पड़ोसी और संबद्ध देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) में सहयोग बढ़ाने के लिए नए द्विपक्षीय करारों का प्रस्ताव किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने कुछ संबद्ध देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय करार भी किए हैं।

(ख) जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला और जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत की हाल की बहुपक्षीय पहलें निम्नानुसार हैं

जलवायु परिवर्तनः

- भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, जी20 देशों द्वारा नई दिल्ली लीडर घोषणा में सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौते को अपनाया गया था, जो सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 4 जुलाई, 2024 को, भारत ने जलवायु परिवर्तन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के साथ एक पर्यावरण संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत स्वीडन के सहयोग से 2019 में लॉन्च किए गए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीड आईटी) के माध्यम से उद्योग डीकार्बोनाइजेशन में सक्रिय रूप से वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। 41 सदस्यों (18 देशों और 23 कंपनियों) के साथ लीडआईटी, कम कार्बन समाधानों की ओर भारी उद्योगों के संक्रमण में तेजी लाने के लिए संवाद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है। दुबई में सीओपी28 (पार्टियों का सम्मेलन) में, भारत और स्वीडन ने लीड आईटी 2.0 और भारत-स्वीडन उद्योग ट्रांजीशन भागीदारी (आईटीपी) लॉन्च की, जो नवाचार, अनुसंधान और वित्तपोषण को बढ़ावा देकर इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने पर केंद्रित है।

आतंकवाद का मुकाबला:

- भारत ने वैश्विक भागीदारों के साथ विचार-विमर्शों के दौरान आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद के खतरे के बारे में अपनी चिंताओं को निरंतर उजागर किया है और वह करारों में परिलक्षित इन चिंताओं के संदर्भ प्राप्त करने में सफल रहा है।
- 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तृतीय नो मनी फॉर टेरर (एनएमएफटी) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण में वैश्विक रुझानों का समाधान किया, जिसमें अवैध धन प्रवाह, फंडिंग के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चैनलों के उपयोग और आतंकवादियों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर वैश्विक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक स्थायी एनएमएफटी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली घोषणा (अक्टूबर 2022) ने आतंकवादियों द्वारा आभासी प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर ज़ोर दिया और यूएनएससी द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। कज़ान घोषणा (अक्टूबर 2024) ने आतंकवाद की निंदा की, इसके राजनीतिकरण को खारिज कर दिया और तकनीकी दुरुपयोग और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया
- आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में इन बहुपक्षीय पहलों ने इस एजेंडे को फोकस में लाया है, राष्ट्रों के सौहार्द के बारे में जागरूकता बढ़ाई है और भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन हासिल करने में मदद की है. इसने भारत के लिए सकारात्मक नेरेटिव निर्माण में भी मदद की है।
- इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने 46 देशों के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) और एक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्नीकल एण्ड इकॉनोमिक कोआपरेशन (बीआईएमएसटीईसी) कन्वेंशन तथा सुरक्षा सहयोग, नारकोटिक ड्रग्स तथा अन्स संबंधित क्षेत्रों में 44 द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किये हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य:

- भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं को दर्शाने के लिए जी 20, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) और जी 7 बैठकों जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भाग लिया है। ये भागीदारी डिजिटल स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, टीबी के टीके विकसित करने, 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का समाधान करने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा और बेहतर देखभाल प्रणाली, स्थायी प्रथाओं और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश की आवश्यकता सम्बंधी जोर देने सम्बंधी भारत के दृष्टिकोण को उजागर करती है।

(ग) भारत ब्रिक्स की विभिन्न चर्चाओं और प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, मिशन, संबंधित मंत्रालय और भारतीय नेतृत्व आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के तहत आयोजित विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों/शिखर सम्मेलनों तथा बहुपक्षीय बैठकों/शिखर सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं। आपसी हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों द्वारा सहमत पहलों, परियोजनाओं और गतिविधियों को लागू करने के लिए कार्य योजनाएं विकसित की गई हैं। आसियान-भारत साझेदारी को 2022 में व्यापक रणनीतिक भागीदार स्तर तक बढ़ा दिया गया है, जो आसियान के साथ किसी भी संवाद भागीदार देश की भागीदारी का उच्चतम स्तर है।

*****